Implementation of Tata Committee Report

*169. SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) is it not a fact that inter-cadre rivalry in communications wing of the Civil Aviation Department has further delayed the smooth implementation of the Tata Committee Report and has aggravated bitterness among the staff all over the country; and

(b) if so, steps taken by Government in this connection?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI A. P. SHARMA): (a) No Sir.

(b) Representations have been received from different Unions/Associations on the question of merger or otherwise of the technical and operational cadres in the communications wing of the Civil Aviation Department. The Empowered Committee constituted for the implementation of the recommendations of the Tata Committee is examining these representations.

A decision on the question of menger or otherwise will be taken as soon as this examination is completed.

Export Import Bank

*170. SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY:
SHRI SHIV KUMAR SINGH:

Will tthe Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the scheme of joint financing of Export and Import Bank by the Reserve Bank of India and Industrial Development Bank of India has run into serious difficulties;

(b) if so, what are the points of difference;

(c) whether the setting up of the Export-Import Bank has now been shelved;

(d) if so, the main reasons for the same; and

(e) what was the main purpose of this bank and to what extent it would have helped the Indian Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (e). No, Sir. Government have decided to set up an Export Import Bank to assist the financing of the country's international trade. The modalities are being worked out.

जीवन बीमा निगम द्वारा निवेशित राशि

*171. श्रीमती कृष्णा साही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम ने वर्ष 1977–78 तथा 1978–79 के दौरान कुल कितनी राशि का निवेश किया और उसमें से कितनी राशि का निवेश बिहार राज्य में किया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1977–78 और 1978–79 के दौरान बिहार में और कुल मिला कर सभी राज्यों में किए गए नये पूंजी निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सभी राज्य	बिहार
1977–78	392.83	18.75
1978–79	425.75	28.39

राजस्थान में ग्रामीण बैंक खोला जाना

*172. श्री बुद्धि सेन जैन : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ग्रामीण बैंक खोले गये हैं और उनके लिये निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ख) ग्रामीण बैंकों द्वारा ग्रामीणों को अन्य राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त दी गई अन्य विशेष सुविधायें क्या हैं;

(ग) राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर और जैसलमेर जो देश में सबसे अधिक पिछड़े हुये जिले हैं और जहां ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था छिन्न-भिन्न है, में उनके विभाग द्वारा ग्रामीण बैंक खोलने में देरी के कारण क्या हैं; और

(घ) इन पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को वहां ग्रामीण बैंक खोल कर कब पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप वित्तमंत्री (श्री मगनभाई बारोट) : (क) से (घ). इस समय राजस्थान राज्य में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं जिनके कार्यक्षेत्र के भीतर आठ जिले आते हैं। नीचे की सारणी में इन बैंकों का ब्यौरा दिया गया है :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	व्याप्त जिले
1. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर	20-10-1975	1. जयपुर 2. नागौर
2. मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली	6-9-1976	1. पाली 2. सिरोही 3. जालोर
3. शेखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर	7-10-1976	1. सीकर 2. झुनझुनु
4. मरुक्षेत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चूरु		1. चूरु

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना खासकर ग्रामीण समुदाय विशेषत: छोटे/सीमान्तिक किसानों, खेतिहर मजदूरों और देहाती कारीगरों की ऋण संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इन बैंकों के स्थानों का चयन करने के लिए जिन सामान्य सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है उनमें ऋण-अंतराल, सहकारी ऋण ढांचे की स्थिति तथा वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के जाल के फैलाव आदि जैसे पहलू शामिल होने हैं। ये बैंक अपने परिचालन क्षेत्रों में लक्षित समूहों के लिए युक्तिसंगत ब्याज दरों पर ,जो सहकारी बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों के समतुल्य रखी गयी हैं, ऋण का प्रबंध करने के अलावा, जमा रकमों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की तुलना में आधा प्रतिशत अधिक ब्याज भी देते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने के लिए स्थानों का सुझाव, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक संचालन समिति देती है और राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रस्तावों को ध्यान में रखा जाता है। इस समय कुछ अन्य जिलों जैसे भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और बूंदी के संबंध में प्रस्ताव किये गए हैं लेकिन जैसलमेर तथा बाड़मेर जिलों के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है।

Withdrawal of Concessional Rates of Duty Applicable to Khandsari Units

*173. SHRI RAJESH KUMAR SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Central Government have recently withdrawn the concessional rates of duty applicable to Khandsari units working under the normal procedure and have also revised the duty on Khandsari sugar and if so, the reasons thereof;

(b) the number of persons thrown out of employment as a result thereof; and